

धनबाद : पूजा टॉकीज के पास सड़क हादसे में एक की मौत, दो हुए घायल

बाराती बस की चपेट में आ गया था नगर निगम का सफाईकर्मि, लोगों ने घंटों किया सड़क जाम

AGENCY DHANBAD :
धनबाद के बेकारबांध स्थित पूजा टॉकीज के पास बुधवार की सुबह एक बाराती बस ने एक बाइक को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी का करीब पांच घंटे तक सड़क जाम रखा। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रोज की तरह बुधवार की सुबह धनबाद नगर निगम के सफाईकर्मियों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं, घटना के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस को खड़ी कर मौके से फरार हो गया।



सड़क जाम कर बैठे निगम के कर्मी व अन्य

मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कर्मियों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं। जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं, घटना के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस को खड़ी कर मौके से फरार हो गया।

बस पर सवार यात्री भी घटना के बाद बस से उतर गए। मृतक की पहचान नगर निगम सफाई कर्मी बजरंगी भुइयां के रूप में हुई है। तो वहीं घायलों का नाम बिककी भुइयां और फुलवा बताया जा रहा है, सभी निगम के सफाई कर्मी है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने नगर निगम कर्मियों के साथ मिलकर

सड़क पर आगजनी कर बेकारबांध - सिटी सेंटर मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया और सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनाती की गई। पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच आक्रोशित लोगों



बस में फंसी बाइक

को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। धनबाद सांसद दुल्लू महतो और धनबाद विधायक राज सिन्हा के प्रयास के बाद लोग शांत हुए। इसके बाद मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये मुआवजा, नौकरी और पेंशन देने की सहमति के बाद लोगों ने सड़क जाम हटा लिया।

BRIEF NEWS

पूर्व वार्ड पार्षद सरोज भेंगरा का निधन

KHUNTI : खूंटी नगर पंचायत की पूर्व वार्ड पार्षद सरोज भेंगरा का बुधवार को उनके कदमा अमूलपुर स्थित आवास पर हो गया। 54 वर्षीया सरोज ने वार्ड नंबर 16 से नगर पंचायत का चुनाव जीता था। वे पिछले कई दिनों से बीमार थीं। कुछ दिन पहले ही वह पारस अस्पताल से अपना इलाज कराकर घर आई थीं। सरोज के निधन सुनकर पूर्व वार्ड पार्षद अपर्णा हंस सहित कई लोग उनके आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। अपर्णा हंस ने कहा कि सरोज भेंगरा बहुत ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। उन्होंने कहा कि हमने एक अच्छा जनप्रतिनिधि खो दिया है।

जीएम लैंड में बने 25 घर अतिक्रमण की जद में

PALAMU : मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में चनवारी के पास प्लॉट नंबर 886 में सरकारी जमीन पर 20 से 25 मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं। नगर निगम की टीम ने मापी कर इन मकानों को बुधवार को चिन्हित किया। मकानों में रहने वालों को नोटिस देकर खुद से मकान हटाने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद भी मकान नहीं हटने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। मकान को चिन्हित करने के लिए मेदिनीनगर सदर अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर पॉलीकार्प तिकी के नेतृत्व में नोडल पदाधिकारी दिलीप कुमार, निगम के सरकारी अमीन विकास कुमार और जमादार शेरान खान ने दोपहर 12 बजे से लेकर 3 तक सभी मकानों की मापी की। टीम की ओर से बताया गया कि 20 से 25 घरों को चिन्हित किया गया है और लाल दाग लगा दिये गये हैं। ऐसे सभी मकानों में रहने वाले लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बाद अगर लोग खुद से मकान नहीं हटाते हैं तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर मकानों को तोड़ा जाएगा। नगर निगम की इस कार्रवाई से सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों में काफी मायूसी देखी जा रही है। वे प्रेशान हो गए हैं।

चुनुडीह गांव में घुसा हाथी, तोड़ा घर



GHATSILA : थाना क्षेत्र के चुनुडीह गांव में बुधवार को हाथी घुस जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि जंगल से निकल कर हाथी गांव के बीचों-बीच से निकल गया। इससे किसी तरह की बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन हाथी ने भैरव मुर्मू नामक ग्रामीण का घर तोड़ दिया है। गांव में हाथी घुसने की सूचना मिलते ही वन विभाग के मनपाल अमित सेन महतो गांव पहुंचकर घर का मुआयना किया। वनपाल ने बताया कि विभाग द्वारा भैरव मुर्मू को उचित मुआवजा दिया जाएगा। भैरव मुर्मू ने वन विभाग को घर टूटने से हुई क्षति का आवेदन वन विभाग को दिया है। ज्ञात हो कि पहली बार शहरी क्षेत्र में हाथी के घुसने से गांव के लोग सहमे हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक हाथी जंगल की ओर निकल गया था। लोगों का अनुमान है कि झुंड से बिछड़ कर हाथी जंगल से शहर की ओर आया है।

छात्राओं को बांटे गए रियूजेबल सैनिटरी पैड



CHAIBASA : झारखंड के पैडमैन सह सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन की ओर से बुधवार को सदर प्रखंड के उल्क्रमित मध्य नीमडीह में छात्राओं व महिलाओं में रियूजेबल सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। इस पैड का इस्तेमाल अच्छी तरह धोकर और सुखाकर लगभग दो साल तक किया जा सकता है। रियूजेबल पैड का इस्तेमाल कर पैड के निस्तारण से जुड़ी समस्याओं से निपटा जा सकता है। वहीं इससे हर महीने महंगा पैड खरीदने से भी निजात मिल सकेगी। संस्था के संस्थापक तरुण कुमार ने किशोरियों से अपील की कि जिन्हें पैड दिया गया, वे बरसात आते ही एक पैड-एक पेड़ की तर्ज पर एक पेड़ लगाएं। इस मौके पर प्रधान शिक्षक कृष्णा देवगम समेत सुशील कुमार सरदार, गंगाराम लागुरी, कुंती बोदरा, कल्पना गोरगई, एलिस बेक, विकास कुमार, सुकांति गोप, सामुल्ला जामुदा आदि शिक्षक-शिक्षिकाएं व फूलमती देवगम, मनीषा लोहार, जानी बारी, नानो मुंडईया, अलका तांती, शबनम तांती, मीनाक्षी खंडाईत, सुमित्रा बारी, सरस्वती कालुंडिया, सरिता पुरती आदि किशोरियां उपस्थित थीं।

युवती से किया दुष्कर्म, वीडियो कर दिया वायरल, आरोपी फरार

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी रिश्ते में मामा लगाने वाला ध्रुव ऋतुल सिंकू है, जिसने पहले शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फिर घटना का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने चाईबासा के मुफस्सिल थाना में दर्ज शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में ध्रुव ऋतुल सिंकू ने उसे हरिगुट बुलाकर जबरन अपने कब्जे में लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपी ने मोबाइल फोन से उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसे



दिखाकर धमकी दी कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वीडियो को वायरल कर देगा। इसके बाद से आरोपी युवती को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता ने बताया कि दिसंबर 2024 में उसने देखा कि उसका अश्लील वीडियो वाट्सएप पर वायरल हो गया है। जब उसने इस पर आरोपी से सवाल किया, तो उसने धमकाते हुए कहा कि जो करना है, कर ले, पुलिस मेरी जेब में है। पीड़िता का आरोप है कि ध्रुव ऋतुल सिंकू एक रसूखदार परिवार से आता है।

कृषक मित्रों ने किया धरना-प्रदर्शन

AGENCY PALAMU :

पलामू जिले के कृषक मित्र अपनी मांगों को लेकर बुधवार को कृषि विभाग कार्यालय का घेराव किया। घेराव कार्यक्रम बड़ी संख्या में कृषक मित्र शामिल हुए। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए एक साल से बकाया प्रोत्साहन राशि देने और हर महीने मानदेय भुगतान की मांग की। घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजन कुमार दुबे ने किया। संचालन तनवीर आलम ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सारे कृषक मित्र ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर कृषि और किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन राशि से भी वंचित किया जा रहा है। एक साल से प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। उनके ऊपर काम करने वाले कर्मियों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वे एयर कंडीशन में बैठकर काम



कृषि विभाग कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते कृषक मित्र

करते हैं लेकिन कृषक मित्र जो गांव-गांव जाकर काम करते हैं उन्हें सिर्फ छला जा रहा है। इसे बदलित नहीं किया जाएगा। कृषक मित्रों को भी मानदेय देना होगा। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच, खाद, बीज, वितरण विधि से खेती करने, कृषक पाठशाला संचालन करने, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करवाने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, बंजर भूमि को उपजाउ बनाने, कृषि समृद्धि, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सब्जी की खेती किसानों को प्रशिक्षण दिलवाने सहित

अन्य कार्य कृषक मित्रों से कराए जाते हैं। इसके बदले में सरकार की ओर से सिर्फ 1000 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वह भी एक वर्ष से नहीं मिली है। इसकी सारी जवाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी की है, क्योंकि सरकार के साथ-साथ विभाग भी कृषक मित्रों के साथ छल कर रहा है। जिला उपाध्यक्ष कृष्णा बैठा ने कहा कि अगर कृषि विभाग कृषक मित्रों को 15 दिन के अंदर प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं करता है तो हम सभी लोग जून के महीने में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे।

योजनाओं से संबंधित साक्ष्य मिटाने के लिए अलपीटो पंचायत में चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम

23 लाख गबन मामले में मुखिया सहित चार पर एफआईआर



प्रतीकालोक तटवीर

नारायण यादव मुखिया का संबंधी तथा तत्कालीन पंचायत सचिव सरयू पासवान की संलिप्तता पाई गई है।

उक्त सभी योजनाओं का भुगतान अलग-अलग लाभुक समिति के नाम से होना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, विष्णुगढ़ ने इस पर कार्यवाही करते हुए अवैधकताओं द्वारा सरकारी राशि का गबन एवं दुरुपयोग, वित्तीय अनियमित तथा

गड्डे में गिरी बाइक युवती की मौत

KHUNTI : खूंटी-चाईबासा मार्ग पर मुरहु थाना के चमराटोली गांव के पास बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में शोभा मुंडू नामक 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। वह मुरहु थाना क्षेत्र के चमराटोली की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार शोभा बुधवार को अपने एक रिश्तेदार के साथ अपने गांव चमराटोली से खूंटी की ओर आ रही थी। गांव से खूंटी-चाईबासा सड़क पर आते ही वालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक एक गड्ढे में गिर गई। इससे शोभा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बाइक वालक को मामूली चोट लगी। स्थानीय लोगों की मदद से युवती को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया।

बरसात से पहले झारखंड हो जाएगा नक्सल मुक्त : डीजीपी अनुराग गुप्ता

PHOTON NEWS GOMIA : बोकारो जिले के ललपनिया-गोमिया स्थित लुगू पहाड़ की तलहटी पर बसे चोरगांवा के सोसो टोला के पास 21 अप्रैल को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन डाकाबेड़ा में मिली सफलता के बाद बुधवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ललपनिया पहुंचे। उन्होंने ललपनिया स्थित टोटीपीएस के श्यामली अतिथि भवन में ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों को सम्मानित किया। डीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन में मारा गया विवेक नक्सलियों का बड़ा लीडर था। उसके मारे जाने से पूरा इलाका शांत हो गया है। उन्होंने कहा कि बरसात शुरू होने से पहले पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान में मिली कामयाबी का श्रेय कोवरा बटालियन को दिया। कहा कि इनके

महिला ने फंदे पर लटककर की खुदकुशी

KHUNTI : तपकारा थाना क्षेत्र के बाजार टांड निवासी बादल महतो की 22 वर्षीय पत्नी ने मंगलवार की देर रात अपने घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तपकारा थाना की पुलिस को बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिली, तो उसने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार पूजा कुमारी घर के पास ही एक शादी समारोह में गई थी और वहां से खाना खाकर घर लौटी थी। सुबह लोगों को जानकारी मिली की पूजा ने खुदकुशी कर ली। इस मामले को लेकर गांव के लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूजा का पति बादल महतो अपराधिक छवि का व्यक्ति है और जेल भी जा चुका है। बताया जाता है कि लगभग डेढ़ साल पहले पूजा की शादी बादल महतो के साथ हुई थी इस संबंध में तपकारा के थाना प्रभारी नितेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि मध्य देह्या मामला खुदकुशी का प्रतीत होता है।

इन योजनाओं के भुगतान में हुई गड़बड़ी

बीडीओ का कहना कि योजना के तहत कराए गए निर्माण कार्यों का भुगतान अलग-अलग लाभुक समिति के नाम होना चाहिए था। ऐसी 16 योजनाओं को चिह्नित किया गया। इसका भुगतान मार्गनिर्देशिका के विपरीत किया गया है। इसमें हेटली बोदरा में रामदेव यादव के घर से बालेश्वर यादव के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ -60 हजार, हेटली बोदरा में पीसीसी पथ से प्रसादी यादव के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ एक लाख 90 हजार, चौथा में महावीर यादव के घर से छोटे यादव के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ-एक लाख 90 हजार, गुंडरो में मनोज ठाकुर के घर से प्रकाश ठाकुर के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ-एक लाख 90 हजार रुपए, गुंडरो में पारटांड मंदिर से डेगलाल सिंह के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ-एक लाख 2 हजार रुपए, गुंडरो में मनोज सिंह के घर से महेंद्र सिंह के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ-एक लाख, अलपीटो में छतरटांड मंदिर से देवकी यादव के घर तक पेवर्स ब्लॉक पथ एक लाख, हेटली बोदरा के मुकेश यादव के घर से पास पुलिया निर्माण -90 हजार, चौथा में बाराबाट में शमशान घाट निर्माण, 50 हजार रुपये, अलकोपी में चापाकल मरम्मत एक लाख 90 हजार रुपये, उपरेली बोदरा में जल-नल कनेक्शन एक लाख 90 हजार, चौथा में 20 घरों में जल नल पाइप कनेक्शन एक लाख 90 हजार, अलपीटो के पंडित टोला में 10 घरों में जल-नल कनेक्शन- एक लाख 90 हजार, हेटलीबोदरा के पाठक टोला में जल-नल कनेक्शन एक लाख 50 हजार अलपीटो में घटाटांड में जल-नल पाइप कनेक्शन, एक लाख 90 हजार, हेटली बोदरा में सिंह टोला में जलनल पाइप कनेक्शन एक लाख 90 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

अलपीटो पंचायत में चोरी की घटना घटी, जो जांच का विषय



घटनास्थल पर जुटे लोग

फोटोन न्यूज

पलामू में ट्रेन से कटकर महिला ने की खुदकुशी

PALAMU : डालटनगंज रेलवे स्टेशन से सटे आबादगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार को एक महिला ने ट्रेन से कट कर खुदकुशी कर ली। चोपन से रांची जा रही रांची- चोपन इंटरसिटी एक्सप्रेस से कटकर महिला की मौत हुई। सूचना मिलने पर रेलवेकर्मि, राजकीय रेल थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। शव को रेलवे ट्रैक से हटया और पोस्टमार्टम के लिए एमआरएमसीएच में भेज दिया है। महिला की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के दिदरी गांव की रहने वाली 35 वर्षीय शोभा देवी पति संजीव कुमार पांडेय के रूप में हुई है। शोभा पति और बच्चों के साथ हमीदगंज में रह रही थी। पति टैम्पो चलाते हैं। घटना बुधवार की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक महिला आबादगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी थी। इसी बीच चोपन से रांची जा रही ट्रेन को देखकर वह तेजी से पटरी की तरफ गई और सो गई। स्पीड में रहने के कारण ट्रेन महिला के ऊपर से गुजरते हुए स्टेशन पहुंच गई, जिससे महिला का शरीर दो हिस्सों में बंट कर क्षत विक्षत हो गया। चालक ने स्टेशन में घटना की जानकारी दी। उसके बाद राजकीय रेल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। महिला के शव की पहचान कई घंटे बाद हुई। शोभा देवी शादी में शामिल होने के लिए दिदरी गांव गयी थी। वहां से मंगलवार को अपने तीन बच्चों के साथ हमीदगंज लौट गयी थी। पति दिदरी में ही थे।

बरसात से पहले झारखंड हो जाएगा नक्सल मुक्त : डीजीपी अनुराग गुप्ता



जवानों को सम्मानित करते डीजीपी

फोटोन न्यूज

इन जांबाज जवानों को डीजीपी ने किया सम्मानित
ऑपरेशन डाकाबेड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी पर जिला पुलिस, झारखंड जम्माआर, सीआरपीएफ, कोवरा बटालियन के जवानों की खूब प्रशंसा की और उनके नेतृत्व कताओं को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सम्मानित कर हासला बढ़ाया। इनमें 209 कोवरा बटालियन के उप कमांडेंट अंजनी कुमार, बाला मुरुगन, विक्रमाजीत, जिला पुलिस के जितेंद्र कुमार, मंदू कुमार, झारखंड जम्माआर इन्स्पेक्टर जेन मुर्मू, सीआरपीएफ के संजीव कुमार और सरोज कुमार शामिल है। मौके पर एडीजी-ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी ऑपरेशन सीआरपीएफ साकेत कुमार सिंह, आईजी अनूप बिरथरे, बोकारो आईजी माइकल राज एस, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, कोवरा बटालियन के कमांडेंट दीपक भाटी, एसपी मनोज स्वर्गियारी, एसडीओपी बीपन सिंह सहित गोमिया, ललपनिया, महुआटांड, पटरवार, जगेश्वर बिहार, चतरावट्टी थाना प्रभारी व जवान थे।

नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें शीर्ष नक्सलियों को मार गिराया गया जो राज्य की

जिला उद्योग केंद्र में 50 लोगों ने कराया निःशुल्क रजिस्ट्रेशन



शिदिर में रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र देते पदाधिकारी

फोटोन न्यूज

HAZARIBAG : जिला उद्योग केंद्र, हजारीबाग द्वारा बुधवार को जिला उद्योग केंद्र में उद्यम रजिस्ट्रेशन कदम-जागरूकता शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में कुल 50 लोगों का निशुल्क ऑन द स्पॉट उद्यम रजिस्ट्रेशन किया गया और 50 लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज दिए गए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के पंजीकरण को बढ़ावा देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शंभू शरण बैठा, जिला अग्रणी प्रबंधक राकेश आजाद, ईओडीबी मैनेजर श्याम कुमार गुप्ता, चैंबर ऑफ कॉमर्स हजारीबाग के अध्यक्ष शंभूनाथ अग्रवाल एवं प्रतिनिधि तारिक राजा, आरसेटी के साथ-साथ विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर श्याम कुमार गुप्ता जिला उद्योग केंद्र द्वारा क्रियान्वित योजनाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहल पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, पीएमईजीपी, पीएम-एफएमई और माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट जैसी योजनाएं छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

घाटशिला कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रो. एमडीपी सिंह का निधन

GHATSILA : घाटशिला कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य प्रो. एमडीपी सिंह का बुधवार को निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें हृदय और पेट से संबंधित समस्याएं थीं। दो दिन पहले ही उन्हें स्टंट लगा था और हॉस्पिटल से घर आए थे। रात 12.30 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तत्काल उन्हें ब्रह्मानंद अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें फौरन घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वे अपने पीछे पत्नी, एक पुत्री व एक नतिनी छोड़ गए हैं। उनका पार्थिव शरीर पैतृक जगमुई (बिहार) ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।



बिहार) ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

धरों को तोड़ता बुलन्दशेर

जरूरी सामान बाहर निकाल लिए थे। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि 40 वर्ष से वे यहाँ छोटा मकान बनाकर रह रहे थे। रेलवे ने उनका आशियाना तोड़ दिया है। अब वे बेघर हो गए हैं। मकानों को ध्वस्त होते देख लोगों की आँखों में आंसू तक आ गए थे। लोग अपना आशियाना टूटते देखकर काफी निराश थे। इसके साथ ही इंजीनियरिंग विभाग ने खसामहल जगनाथ मंदिर के अंदर के हिस्से में बनी दो झोपड़ी को भी ध्वस्त किया।

राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनमोल योगदान

देश व दुनिया में प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय निर्माण की विचारधारा के दम पर अपनी विशेष पहचान रखता है। यह देश व दुनिया का एक ऐसा संगठन है, जो अपनी विशेष कार्यशैली के दमखम पर दुनिया में सनातन धर्म-संस्कृति के रक्षक तौर पर और एक बहुत बड़े सामाजिक संगठन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। संघ वर्ष 2025 में स्थापना का 100वां वर्ष धूमधाम से मना रहा है और वह दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि संघ भारत का एक ऐसा संगठन है, जो अपनी स्थापना के दशकों बाद भी अपनी विचारधारा व उद्देश्यों से जरा भी नहीं भटका है, वह आज भी अपनी विचारधारा पर पूरी तरह से कायम है। मां भारती के सपूत स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जो आजादी के दौर में विजयदशमी के पालन पर्व के दिन 27 सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना देश, संस्कृति व समाज हित के कार्यों को करने के उद्देश्य से की थी। इस संकल्प के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना काल से लेकर के आज तक देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करने में निरंतर लगा हुआ है। वैसे निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो संघ के द्वारा किए गए कार्यों ने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हुए गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर आजाद हुए भारत देश के निर्माण में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से सकारात्मक योगदान देने का कार्य किया है। अपने शीर्ष नेतृत्व के सशक्त राष्ट्र, सभ्य समृद्धशाली समाज निर्माण के ओजस्वी विचारों के चलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्र निर्माण व सनातन धर्म की रक्षा करने में अनमोल योगदान रहा है। जिस योगदान को हम लोग आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से देख सकते हैं, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संघ ने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर दिन-रात एकजुट होकर काम किया है। हालांकि देश की आजादी के संघर्ष के दौर से लेकर आजाद भारत तक में भी चंद राजनेताओं के क्षणिक राजनैतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ऐसे लोगों के निशाने पर रहा है। ऐसी स्थिति के चलते ही राष्ट्र की आजादी व सशक्त राष्ट्र निर्माण की यात्रा में संघ के स्वयंसेवकों के अनमोल योगदान को दशकों तक सत्ता व सिस्टम में बैठे कुछ लोगों द्वारा अनेरेखा किया गया। देश के चंद राजनेताओं ने धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए संघ को बदनाम करने का कार्य तक भी किया है। यह सब आज भी उनके अनुयायियों के द्वारा जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ राजनेताओं द्वारा पैदा की गई नकारात्मक स्थिति के बाद भी राष्ट्र व समाज हित के लिए अपना कार्य हमेशा निस्वार्थ भाव से करना जारी रखा और कभी भी संघ के इन स्वयंसेवकों ने इन कार्यों का श्रेय लेने तक का भी प्रयास नहीं किया। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त सरकारों के दौर में शासन व प्रशासन द्वारा बार-बार विकट स्थिति उत्पन्न करने के बावजूद संघ के स्वयंसेवकों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्थापना काल के दौर से ही राष्ट्र निर्माण, एकता और सांस्कृतिक जागरण के दीप को प्रज्वलित करते हुए समाज को संगठित करने और सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने पर जोर दिया है। जर्गे आजादी के दौर में संघ ने जहां लोगों को राष्ट्रभक्ति के भाव से ओतप्रोत करने का कार्य बखूबी किया था, वहीं आजाद भारत में संघ ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के प्रयास करते हुए एकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य निरंतर किया। देश के दूरदराज ढांचों तक में भी अपनी 55000 शाखाओं व करोड़ों स्वयंसेवकों के माध्यम से पहुंच कर संघ ने देश के युवाओं के एक बहुत बड़े वर्ग को अनुशासन में रहना सिखाते हुए उनमें नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यों की बानगी देखें तो जगे आजादी के दौर में संघ ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान देते हुए समाज में राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने का काम बखूबी किया था। संघ ने वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की बड़-चढ़कर के सहायता करते हुए उन लोगों के जान-माल की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया। संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए महामारी के दौर में लोगों की बड़-चढ़कर के मदद की। संघ व उसके अन्य सहयोगी संगठनों ने समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, चक्रवाती तूफान आदि), युद्ध और अन्य राष्ट्रीय संकटों के समय हमेशा राहत व बचाव के कार्यों में बड़-चढ़कर के सक्रिय भूमिका निभाई। आज के व्यवसायिक दौर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विभिन्न संगठन जैसे विद्या भारती, सेवा भारती जैसे संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कार्यरत हैं। विद्या भारती जैसे संघ के संगठनों ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य पूरे देश में चला रखा है। देश में हजारों स्कूलों के माध्यम से लाखों छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा निरंतर प्रदान की जा रही है। शिक्षा के माध्यम से नैतिकता, देशभक्ति और सामाजिक समरसता जैसे मूल्यों को युवा पीढ़ी में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

डिग्री नहीं, दक्षता चाहिए : नई अर्थव्यवस्था की नई जरूरतें



डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या वाला देश है। यह जनसांख्यिकी लाभार्थ एक वरदान बन सकता है, यदि हम इसे कुशलता, योग्यता और आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करें, परंतु अफसोस कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक गहरे संकट से जूझ रही है। विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है और उद्योगों को जो चाहिए, इन दोनों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। यह खाई केवल छात्रों की रोजगार क्षमता को ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी गंभीर रूप से बाधित कर रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट- 2024 के अनुसार, भारत में केवल 45.9 प्रतिशत स्नातक ही रोजगार के योग्य पाए गए। इसका अर्थ यह है कि हर दो में से एक छात्र, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वह नौकरी के लायक कौशल से तैस नहीं है। तकनीकी संस्थानों की स्थिति भी निराशाजनक है। नैसर्गिक की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातक ही आईटी सेक्टर में कार्य के लिए उपयुक्त पाए गए। यह स्थिति न केवल शिक्षा प्रणाली की विफलता है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपनों के टूटने की त्रासदी भी है। इस समस्या की जड़ है, सैद्धांतिक और अकादमिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा प्रणाली, जो व्यावहारिक दुनिया की जरूरतों से कटी हुई है।

वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रणाली उद्योग की तेजी से बदलती आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर स्नातक रोजगार के लिए अयोग्य माने जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं, जबकि तकनीकी क्षेत्र में भी यह आंकड़ा बहुत कम है। विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रमों को नियमित रूप से उद्योग के विशेषज्ञों से समीक्षा कराना चाहिए, ताकि छात्रों को भविष्य की नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा में मानवीय मूल्यों, सॉफ्ट स्किल्स और सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को न केवल पेशेवर, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच अधिक समन्वय से भारत को एक अधिक सक्षम, समावेशी और प्रतिस्पर्धी कार्यबल मिल सकता है, जो देश को 2047 तक एक विकासशील राष्ट्र बनने में मदद करेगा। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या वाला देश है। यह जनसांख्यिकीय लाभार्थ एक वरदान बन सकता है, यदि हम इसे कुशलता, योग्यता और आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करें, परंतु अफसोस कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली आज एक गहरे संकट से जूझ रही है। विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है और उद्योगों को जो चाहिए, इन दोनों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। यह खाई केवल छात्रों की रोजगार क्षमता को ही नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी गंभीर रूप से बाधित कर रही है। इंडिया



स्किल्स रिपोर्ट- 2024 के अनुसार, भारत में केवल 45.9% स्नातक ही रोजगार के योग्य पाए गए। इसका अर्थ यह है कि हर दो में से एक छात्र, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वह नौकरी के लायक कौशल से लैस नहीं है। तकनीकी संस्थानों की स्थिति भी निराशाजनक है। नैसर्गिक की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25% इंजीनियरिंग स्नातक ही आईटी सेक्टर में कार्य के लिए उपयुक्त पाए गए। यह स्थिति न केवल शिक्षा प्रणाली की विफलता है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के सपनों के टूटने की त्रासदी भी है। इस समस्या की जड़ है, सैद्धांतिक और अकादमिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा प्रणाली, जो व्यावहारिक दुनिया की जरूरतों से कटी हुई है। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम दशकों पुराना है, जो आज के डाटा संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेरित, नवाचार प्रधान उद्योग की जरूरतों से मेल नहीं खाता। आज की नौकरियां पहले जैसी नहीं रहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन,

अनुरूप शिक्षा दे सके। सभी विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में औद्योगिक इंटरशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और केस स्टडी आधारित मूल्यांकन शामिल करना चाहिए। तकनीकी और मानवीय विषयों का समावेश : केवल तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, संवाद क्षमता, टीमवर्क, सहानुभूति और नेतृत्व जैसे तत्वों का भी विकास किया जाना जरूरी है। कंपनियां विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रिसर्च लैब्स, इन्वोवेशन हब और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करें, जैसा कि आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क इसका उदाहरण है। भारत को यह समझना होगा कि अकेले तकनीकी शिक्षा से संपूर्ण विकास संभव नहीं। हमें वैश्विक मॉडलों से सीखना चाहिए। जर्मनी का ड्यूल एजुकेशन सिस्टम एक शानदार उदाहरण है, जहां सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय छात्रों को उद्योग के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार अमेरिका में सापुदायिक कॉलेजेज और स्टार्टअप एक्सलेरेटर शिक्षा को उद्योग से जोड़ते हैं। सिंगापुर जैसे देश में हर तीन साल में कौशल समीक्षा होती है और शिक्षा उद्योग के सहयोग से चलती

है। भारत को भी एक ऐसा ही डायनामिक करिकुलम फ्रेमवर्क अपनाने की जरूरत है। हालांकि इस दिशा में कदम उठाने के अपने खतरे भी हैं। यदि हम शिक्षा को केवल उद्योग की आवश्यकता तक सीमित कर दें तो हम भविष्य के नागरिक नहीं, केवल कर्मचारी तैयार करेंगे। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति हो सकती है। अत्यधिक व्यावसायिकता छात्रों की रचनात्मकता और नैतिक सोच को कुंद कर सकती है। साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र जैसे विषयों को अगर गैर उपयोगी मानकर नजर अंदाज किया गया तो शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। लगातार पाठ्यक्रमों में बदलाव, तकनीकी उन्नयन और उद्योग सहभागिता विश्वविद्यालयों के लिए महंगा साबित हो सकता है, जिससे ग्रामीण और वंचित तबकों की पहुंच सीमित हो सकती है। भारत सरकार ने रिकल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं चलाई हैं। इन अभियानों की सफलता तभी संभव है, जब उच्च शिक्षा प्रणाली कुशल, समावेशी और उद्यमशील मानव संसाधन तैयार करें। यह तभी हो सकेगा जब विश्वविद्यालय शिक्षा को उद्योग की जरूरतों से जोड़ने की रणनीति राष्ट्रीय प्राथमिकता बने। यह संरिखण केवल तकनीकी प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें नैतिकता, सहानुभूति, संवाद और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को भी सम्मिलित करना होगा। तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी सक्षम, सामाजिक रूप से समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

प्राइवेट स्कूल का शिक्षक और उसकी मूक पीड़ा

जब भी परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो अमूमन सरकारी स्कूलों के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों के परिणाम बेहतर होते हैं। इसके पीछे इन स्कूलों के जवानों की कड़ी मेहनत होती है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों से उम्मीदें तो आसमान छूती हैं, लेकिन उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है, न सम्मान, न छुट्टी और न ही सुरक्षा। महिला शिक्षक दोहरी जिम्मेदारियां उठाती हैं, वहीं शिक्षक दिवस के दिन सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान मिलता है, जबकि सालभर उनका कथित तौर पर शोषण जारी रहता है। अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकार तीनों ही इस शोषण को नजरअंदाज करते हैं। शिक्षक के अधिकारों की कोई बात नहीं करता, न ही कोई नियामक संस्था है, जो उनके हितों की रक्षा करे। शिक्षकों को कानूनी संरक्षण, संगठित मंच और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, ताकि शिक्षा प्रणाली सच में समावेशी और न्यायपूर्ण बन सके। यदि राष्ट्र को शिक्षित और सशक्त बनाना है, तो सबसे पहले शिक्षक

को शोषण से मुक्त करना होगा, क्योंकि चाँक से लिखा हर अक्षर, देश का भविष्य गढ़ता है। एक समय या जब गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय जैसे दोहे बच्चों की जुबान पर होते थे। आज हाल ये है कि अगर मास्टर मोबाइल पकड़ लें तो कहा जाता है कि इतनी फुर्सत है तो बच्चों को क्यों नहीं संभालते। जमाना बदल गया है, अब शिक्षक शब्द पवित्रता नहीं, सहनशीलता का प्रतीक बन गया है। इस सहनशीलता का सबसे क्रूर रूप दिखता है प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की दुनिया में। बाहर से देखिए तो प्राइवेट स्कूल किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगते। एसी क्लासरूम, हाईटेक बोर्ड, इंग्लिश बोलते बच्चे और व्हाइट ग्लस्स पहने बस अंडेंटेंड्स। लेकिन, अंदर झाँकिए, वहां एक मास्टर साहब बैठे हैं, जो न वक्त पर चाय पी सकते हैं, न लंच कर सकते हैं। जो बच्चा होमवर्क न करे, उसकी शिकायत आए तो मास्टर की क्लास लगती है। जो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो मैनेजमेंट पृष्ठता है क्यों पढ़ाया नहीं ढंग से। प्राइवेट

स्कूलों में सैलरी का सिस्टम इतना गोपनीय है कि सिक्रेट एजेंसियां भी शरमा जाएं। अपॉइंटमेंट लेटर पर 25,000 रुपये लिखा होता है, लेकिन बैंक में महज 8,000 रुपये ही ट्रान्सफर होते हैं। बाकी कैश में मिलते हैं या कभी नहीं मिलते। पत्रों की बात देखिए कि टीचर जब सैलरी का हिसाब मांगता है, तो जवाब होता है, नौकरी चाहिए या नहीं। यदि शिक्षक महिला है तो फिर दिक्कतों की भरमार है। घर में बहु, मां और पत्नी। स्कूल में मैडम, टीचर और दीदी। महिला शिक्षकों को दोहरी जिम्मेदारी के साथ जीना पड़ता है। सुबह पांच बजे से घर संभालो, फिर स्कूल जाओ और वहां 40 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। ऊपर से अगर पति भी प्राइवेट सेक्टर में हो तो महीने की सैलरी से पहले ही घर का बजट गिरवी रख देना पड़ता है। प्राइवेट शिक्षक की दुश्वाहियां यहीं खत्म नहीं होतीं। सरकारी कैलेंडर कहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल कहता है कि आओ, झंडा फहराओ,

भाषण दो, फिर हाजिरी लगाओ और जाओ। छुट्टी के दिन भी हाजिरी की मजबूरी। अगर बीमार पड़ गए तो प्रबंधन कहेगा कि छुट्टी नहीं है, डिडक्शन लागेगा। शिक्षक का गला बैठ जाए, तब भी कहा जाता है कि क्लास तो लेनी ही होगी और कोई नहीं है। आज शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि वह क्लास टीचर है, परीक्षा नियंत्रक है, अभिभावक संवाद अधिकारी है, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन है, स्पोर्ट्स डे का आयोजक है और हर हफ्ते सेल्फी वाले वीडियो का संपादक भी। लेकिन, जब सैलरी की बात आए तो कहा जाता है कि आप तो सिर्फ दो पीरियड पढ़ाते हैं। बच्चा अगर टॉप करे तो प्रिंसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमारे स्कूल का वातावरण ही ऐसा है। यदि बच्चा फेल हो जाए तो मास्टर की जवाबदेही तय होती है। कहा जाता है कि आपने ठीक से पढ़ाया नहीं। जीत स्कूल की, हार शिक्षक की। फोटो बैनर पर प्रिंसिपल की, मेहनत मास्टर की। आजकल अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षक तीन महीने में उनके बच्चे को

अधिकारों की बात कौन करे। क्या कोई आटीआई लगा सकता है कि मास्टर को उचित सैलरी मिल रही है या नहीं, क्योंकि शिक्षक अधिकारों की बात करना आज भी असहनीय माना जाता है। अब वक्त आ गया है कि शिक्षक चुपी तोड़े। सरकार को चाहिए कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, जो प्राइवेट स्कूलों की सैलरी, काम के घंटे, छुट्टियां और काम का बोझ तय करे। हर जिले में निजी शिक्षकों की यूनियन बने जो एक स्वर में बोलें। अभिभावकों को भी समझना होगा कि शिक्षक सिर्फ एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, बल्कि उनके बच्चे के भविष्य का निर्माता है। देश को अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले उस हाथ को संभालना होगा जो ब्लैकबोर्ड पर चाँक से भविष्य रचता है। उस आवाज को सुनना होगा जो हर दिन गुड मॉर्निंग कहकर बच्चे को दिन की शुरुआत सिखाता है। शिक्षक की मुस्कान में देश की मुस्कान छिपी है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द है, ये जानने वाला कोई नहीं।

Social Media Corner

सच के हक में...

पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दु:ख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूँ कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।

(गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कारयाराना आतंकी हमले की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ एवं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना निंदनीय कृत्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस कारयाराना हमले को अंजाम देने वाले किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा।

(बाबूलाल मराडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

टकराव की राह पर विधायिका-न्यायपालिका

तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई आलोचना ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच फिर एक बार टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से विधानसभा में पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल की सहमति से रोके रखने का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। अपने अनुरे निर्णय में न्यायालय ने न सिर्फ इन लंबित विधेयकों को राज्यपाल की सहमति के बिना ही मंजूर घोषित किया, बल्कि राज्यपाल के लिए तीन माह के भीतर ऐसे बिलों को वापस विधानसभा भेजने अथवा राष्ट्रपति के समक्ष विचार हेतु प्रेषित करने की समयसीमा भी निश्चित कर दी। इतना ही नहीं, न्यायालय ने अपने फैसले में राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया कि उन्हें राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ राज्य अवलगत जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने राज्यपाल की शक्तियों का अधिग्रहण कर विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप तो किया ही, संघीय ढांचे में केंद्र की ओर शक्ति के झुकाव को भी कुंद किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने

इसी पर आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा के घर मिले अधजले नोटों के मामले में कोई एफआईआर न दर्ज किए जाने पर भी प्रश्न खड़े किए। समावर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्रीय कानूनों की सर्वोच्चता, सातवीं अनुसूची में शामिल होने से रह गए अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार ऐसे कुछ प्रविधान हैं, जो केंद्र की सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। अनु. 355 एक ऐसी शासकीय व्यवस्था की कल्पना करता है, जिसमें केंद्र पर यह सुनिश्चित करने का भार होता है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व का पालन संवैधानिक प्रविधानों के अनुरूप करें। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति की अथवा राज्यपाल के पास कहीं अधिक और वास्तविक शक्तियां होती हैं। कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने या फिर असंवैधानिक कार्यकलापों का मामला संज्ञान में आने पर वह अथवा राज्यपाल भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु राज्यपाल के समक्ष आए विधेयकों को अनुमति देने या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित रखने की कोई सीमा

नहीं है। जिन 10 विधेयकों को लेकर राज्य सरकार ने याचिका दायर की, उनमें एक विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन का अधिकार राज्यपाल से हटाकर मंत्री परिषद को देने की बात करता है। ऐसे में याचिका का दायरा सीमित कर विषय केन्द्रित किया जा सकता था, परंतु राज्यपाल और राष्ट्रपति, दोनों के लिए प्रत्येक विधेयक को अनुमति की समयसीमा में बांधे जाने से न केवल अशुद्ध नसीब मदनी की रिहाई का प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राष्ट्र की एकता और अखंडता को दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है। हाल में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा है।

उल्लेखनीय सहमति

तकरीबन साढ़े तीन वर्षों और बैठकों के 13 दौर के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देश महामारियों (पैंडेमिक) की रोकथाम, उनके लिए तैयारी और उन पर प्रतिक्रिया के उपायों पर सहमत हो गए हैं। अभी 16 अप्रैल को अंतरसरकारी वार्ता निकाय ने डब्ल्यूएचओ के महामारी संबंधी समझौते के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। दुनिया को ज्यादा महफूज बनाने के लिए पीढ़ीगत समझौते के रूप में वर्णित यह मसौदा अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया जाने के लिए तैयार है। हालांकि डब्ल्यूएचओ द्वारा पहले प्रस्तावित महत्वाकांक्षी मसौदे की बनिस्पत इसका दायरा सीमित है, फिर भी ग्लोबल नॉर्थ और विकासशील देशों की भिन्न प्राथमिकताओं व बाध्‍यताओं के मद्देनजर यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, खासकर यह देखते हुए कि जनवरी से अमेरिका डब्ल्यूएचओ का हिस्सा ही नहीं है। जहां विकासित देश निदान (डायग्नोस्टिक), उपचार, वैक्सीन और तकनीक हस्तांतरण पर पीछे हट गए, वहीं विकासशील देशों ने साझा की गई सामग्री के इस्तेमाल से विकसित जांच, उपचार और वैक्सीन तक सुनिश्चित पहुंच मिले बगैर रोगाणु नमूने और जीनोम सीक्वेंस साझा करने में हिचकिचाहट दिखाई। ये असहमतियां याद दिलाती हैं कि किस तरह इंडोनेशिया ने 2000 के दशक के मध्य में उस असहमतापूर्ण एच5एन1 नमूना साझाकरण तंत्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, जिसमें उसके नमूनों के इस्तेमाल से विकसित वैक्सीन तक समतापूर्ण और वहनीय पहुंच नदारद थी। पहला अनुच्छेद जिस पर सभी देश सहमत हुए, वह था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े कर्मियों की बेहतर सुरक्षा की प्रतिबद्धता। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रोगाणुओं तक पहुंच और लाभ साझा करने की प्रणाली पर हर देश को सहमत करना था। रोगाणु नमूने और जीनोम सीक्वेंस डाटा साझा करने वाले विकासशील देशों को इस नमूने अथवा डेटा के इस्तेमाल से विकसित किसी भी निदान, वैक्सीन या उपचार तक पहुंच की गारंटी दी गई है।

‘Sharbat jihad’: HC pulls up Patanjali, says ‘can’t believe eyes and ears’

As court says its "conscience shaken", Patanjali says it will pull down videos allegedly against Rooh Afza

New Delhi. THE DELHI High Court Tuesday directed Baba Ramdev's Patanjali to immediately pull down all its advertisements allegedly referring to Hamdard's popular drink Rooh Afza as "Sharbat Jihad," saying they "shocked the conscience of the court". "I couldn't believe my eyes and ears," Justice Amit Bansal, who was hearing the case, said about Patanjali's videos. Senior advocate Rajiv Nayar, appearing for Patanjali, told the court that the videos will be pulled down. When the case first came up in the court Tuesday morning, Justice Bansal observed: "This is shocking. Shocking. It shocks the conscience of the court. Please take instructions immediately. This is indefensible according to me. Take instructions, otherwise there will be a strong order."

Hamdard, through its charity wing Hamdard National Foundation India, has moved a suit claiming trademark infringement and disparagement, as well as defamation against Patanjali Foods Limited and Baba Ramdev, citing a video that showed Ramdev claiming that his competitor's profits were used "for building masjids and madrasas." Profits from Patanjali's "rose sharbat", he said, go towards building "gurukuls, acharyakulams and Patanjali University". "Jaise love jihad, vote jihad chal raha hai naa, waise sharbat jihad bhi chal raha hai (Like there is love jihad and vote jihad, there is sharbat jihad)," Ramdev added. Hamdard, in its suit, is also seeking a



permanent injunction restraining Patanjali from infringing and disparaging its trademark, damages upto Rs 2 crores, as well as seeking an apology and retraction. It is also seeking the court's direction to the Ministry of Electronics and Information Technology and the Department of Telecommunications (DoT) to take down the links of the objectionable material. Appearing for Hamdard, senior

advocate Mukul Rohatgi Tuesday read out tweets and the content of the video, where Ramdev allegedly makes a reference to Rooh Afza. Rohatgi added: "Hamdard requires no elaboration... We have all grown up with Rooh Afza. This is a case which is shocking, this goes beyond disparagement, it goes beyond normal cases. This is a case creating communal divide, it is akin to hate speech. This is commercial speech and will not have protection under the law of defamation... You cannot go about branding whatever you want... He says 'sharbat jihad'. Jihad is a war in the name of religion, so you are attacking my religion, because it is well known that Hamdard belongs to people of the Muslim community."

Delhi HC quashes charge against mother who delayed reporting sexual abuse

NEW DELHI. The Delhi High Court clarified that Section 21 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act is meant to prevent the concealment of child sexual abuse and ensure timely reporting in the child's best interest. It is not intended to punish those who, despite their personal struggles, eventually come forward. Justice Swarana Kanta Sharma, in her judgment, stated, "If judges begin to treat delay and silence — caused by trauma or social oppression — as criminality, we risk turning the protective intent of the law into an instrument of oppression itself. Justice cannot be sacrificed for technicalities." Section 21 of the POCSO Act addresses the failure to report or record incidents of sexual offences against minors. It allows punishment by imprisonment, fine, or both for those who neglect to report such offences. This case involved a mother charged under Section 21 after her minor daughter alleged sexual assault by her father and two sons of her sister-in-law. The mother also claimed she was physically assaulted by her in-laws. An FIR was filed after the child's statement. During the investigation, it was noted that the mother had made three PCR calls about physical abuse by her in-laws but had not mentioned the sexual assault on her daughter. Based on this, charges under Section 21 were brought against her. However, the Court found this charge to be flawed and allowed the mother's plea. It ruled that she had not tried to protect the accused but was also a victim of domestic violence by the same people she was expected to report. The Court also emphasised that the child's medical examination and legal proceedings were initiated only because the mother eventually intervened.

Delhi sees warm and dry day, no relief in sight as temperature could rise further

NEW DELHI. The capital experienced another hot and dry day on Tuesday, with temperatures nearing 40°C and clear skies prevailing across the region. The India Meteorological Department (IMD) reported that the Safdarjung observatory recorded a maximum temperature of 39.9°C and a minimum of 20.9°C, both above normal. While maximum temperatures remained 2–3°C above normal across most stations, a sharp dip in night temperatures was observed. Lodi Road, for



instance, recorded a minimum of 18.4°C, around 4°C below normal. No rainfall was reported anywhere in the NCR over the last 24 hours, and humidity levels ranged from 13% to 51%. The IMD has forecast a rise in maximum temperatures by 1–2°C over the next two days, with heatwave conditions likely to set in from April 24 onwards. From Wednesday through Saturday, several districts of Delhi—including Central, North, South, and East—are expected to see heatwave conditions, with daytime temperatures climbing up to 43°C. Despite no official heatwave on Tuesday, the IMD has flagged clear skies and sustained surface winds (10–20 km/h), which may provide some relief. Westerly to northwesterly winds continued to dominate the region. The IMD has urged citizens to avoid prolonged sun exposure, stay hydrated, and take precautions, especially for vulnerable groups like children, the elderly, and those with pre-existing conditions.

Dry promises: Tap water eludes UP's Bundelkhand despite government claims

New Delhi. Despite rapid infrastructure development, the issue of clean drinking water continues to plague Uttar Pradesh's Bundelkhand. Residents of Chureh Kesharva village in Chitrakoot are facing an acute shortage. Taps, tube wells, and hand pumps dot the villages, but water remains scarce, forcing women and children to travel long distances to fetch it. The seriousness of the situation can be gauged by the fact that a nine-year-old girl, Annu, carries multiple 20-litre buckets of water daily, despite weighing only 15 kg. Her mother attributes their struggle to incomplete tap connections, saying, "The family's plight is due to incomplete tap connections." Similarly, Ranjana, a 12th-grade student in the village, relies on hand pumps for water. She repeatedly fills bucket after bucket, demonstrating her endurance in the face of adversity. "They promised water connections that never materialised," a resident said, frustrated by the negligence affecting her community. The progress in providing tap water connections under Jal Jeevan Mission in Uttar Pradesh is slow. The Chitrakoot District Magistrate said that efforts are underway to improve supply, promising, "Plans are in place to saturate the area with tap water connections within six months." The Jal Jeevan Mission has approved 40,951 schemes in Uttar Pradesh, with a total budget of Rs 1,52,521.82 crore. Officials have reported 100 per cent tap water coverage in 24,576 villages, benefiting over 4.86 crore people. However, the stark reality in Chitrakoot tells a different story, exposing the gap between policy promises and everyday struggles.

Delhi AQI worsens: Environment minister Sirsa calls it a 'health emergency', orders crackdown on polluters

NEW DELHI. In response to the worsening air quality in the capital, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa on Monday held an emergency review meeting and ordered immediate action against high-polluting industries, institutions, and construction sites. Chairing the meeting with senior officials from the Environment Department and the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), Sirsa expressed concern over the rising Air Quality Index (AQI) and termed the situation a "health emergency." He instructed officials to take swift and time-bound action to mitigate



pollution, including the suspension of construction work at sites flouting dust control norms. Authorities were directed to identify and act against major sources of emissions, while ensuring that mitigation measures were implemented without delay. As part of immediate interventions, Sirsa asked officials to deploy water sprinklers and anti-smog guns at large construction zones and pollution hotspots. He also stressed the importance of monitoring air quality in sensitive areas, particularly around schools and hospitals, using real-time data. "Environmental responsibility is not on one department but a collective duty of all," Sirsa said, urging stronger inter-departmental coordination. He also directed the Municipal Corporation of Delhi and the DPCC to submit daily progress reports and warned that repeated violations would invite strict penalties. Highlighting the role of civic engagement, Sirsa called for enhanced public awareness campaigns targeting Resident Welfare Associations (RWAs), market bodies and construction agencies.

Delhi to double Wazirabad pond capacity in major desilting push

NEW DELHI. In an effort to enhance Delhi's water supply, the Delhi Jal Board (DJB) has initiated a large-scale desilting project aimed at increasing the storage capacity of the Wazirabad pond, a key raw water source in the capital. The initiative, expected to significantly boost water production, comes at a time when the city continues to fall short of its daily water requirement. Earlier this month, Water Minister Parvesh Verma visited the Wazirabad water treatment plant and announced the government's plan to take up desilting operations in the pond area located in North Delhi. The DJB has since floated a Rs 25 crore tender to remove 3.63 lakh cubic metres of accumulated silt, which officials say has drastically reduced the pond's holding capacity. "The work

will be carried out upstream of the river, starting from Wazirabad up to Ramghat, which is a distance of around 1 km. Usually, during the monsoon season, silt is carried away downstream, but this is legacy silt,



which has accumulated over the years," a DJB official explained. Once the desilting is complete, a process expected to take two months, the pond's storage capacity is projected to nearly double, adding around 100

million gallons per day (MGD) of holding space. The Wazirabad barrage serves as the first interception point of the Yamuna River within Delhi and feeds one of the largest water treatment plants in the city.

While the WTP is designed for a 220 MGD capacity, it currently functions at under half that due to silt-related limitations. "The Wazirabad WTP has a storage capacity of 220 MGD, but due to silt accumulation along a one-km stretch, it is currently holding only around 100 MGD," Verma said. Water production in the capital has grown steadily — from 927 MGD in 2020-21 to around 990–1,000 MGD in 2024 — yet still lags behind

the estimated 1,290 MGD demand, as highlighted in the Economic Survey. During his earlier inspection, Verma drank treated water at the facility to demonstrate its safety. He also stressed the need for improved infrastructure.

Launch of Delhi e-buses put off due to mourning for Pope

NEW DELHI. The city government postponed the launch of the Delhi Electric Vehicle Interchanges (DEVI) on Tuesday following the Centre's declaration of national mourning in the wake of the passing of Pope Francis. The Delhi Transport Department officials said the inauguration will be announced with a revised date soon. DEVI buses, which were earlier proposed to be named "Mohalla Buses" by the previous AAP government, will soon hit the road. These buses were undergoing trial runs on half a dozen routes over the past few months.

In its first phase, 76 buses will be operated from three depots — Nangli, East Vinod Nagar, and Ghazipur. Each bus is designed to seat 23 passengers,



with an additional standing capacity for 13 individuals. Importantly, six seats will be reserved for women, and 25 per cent of the total seating will be made available free of cost under the Delhi government's Pink Pass scheme, aimed at encouraging safer and more affordable travel for women.

The buses are powered by a battery system comprising six battery packs

with a combined energy capacity of 196 kWh. A full charge can be completed in 45 minutes, providing a driving range of up to 200 km — sufficient for a full day's operations within city limits. The first operational route under the DEVI scheme, labelled MS-1, is planned to connect Akshardham Metro Station with the Mayur Vihar Phase-3 Paper Market. Key stops along this corridor include densely populated residential and commercial zones such as Trilokpuri, Kalyanpuri, and Ghazipur, offering much-needed connectivity to underserved areas.

The fare structure will mirror that of the capital's existing fleet of air-conditioned buses, with tickets priced at Rs 10, Rs 15, Rs 20, and Rs 25 depending on the distance travelled.

Only active Muslim bar council members eligible for Waqf board role: Supreme Court

The Supreme Court held that a Muslim member of a state bar council should be an active member to be eligible to serve on the state Waqf Board.

NEW DELHI. The Supreme Court on Tuesday held a Muslim member of a state bar council ceases to be eligible to serve in the state Waqf Board if he is no longer holding the position in the bar body. A bench comprising Justices M M Sundresh and Rajesh Bindal was dealing with the question of whether a person who ceases

to be a Muslim member of a bar council could continue to remain a member of the waqf board.

Setting aside the judgement of a division bench of the Manipur High Court, the top court said, "There are twin conditions to be eligible to be a Member of the Board: (1) The candidate must be from the Muslim community; and (2) must hold an active position as a Member of Parliament, State Legislative Assembly, or Bar Council. If a person no longer fulfils these conditions, they cannot continue to hold the Board position (sic)."

The case related to an appeal by one Md Firoz Ahmad Khalid, who was appointed a member of the Manipur Waqf Board in February 2023 following his election to the Manipur bar council. He replaced another person who lost his position in the bar council after elections in December

2022.

While a single judge of the high court upheld Khalid's appointment, the division bench reversed the decision, ruling the law did not explicitly require a bar council



member to vacate their position on the Waqf Board upon ceasing to be a bar council member. Writing a 25-page judgement, Justice Sundresh disagreed

with the impugned verdict of the division bench. The judgment clarified that an ex-member of the bar council can be considered for Waqf Board membership only if there are no serving Muslim members in the bar council at present — a special exception under the second proviso to Section 14(2) of the Waqf Act. As a result, the bench reinstated the single judge's decision, upholding Khalid's appointment as member of the state Waqf Board. "We also note that presently, the appellant is the only Muslim member in the bar council concerned - a fact that has been rightly taken note of by the state of Manipur, while appointing him as a member of the board. In any case, there is no dispute with respect to the appellant's eligibility to be a member of the board by virtue of his membership in the bar council," it said.

NEWS BOX

"Unacceptable": UN Chief Condemns Pahalgam Attack That Killed 26 Tourists

United Nations.UN Secretary General Antonio Guterres has strongly condemned the "armed attack" in Pahalgam in Jammu and Kashmir, stressing that attacks against civilians are unacceptable under any circumstances."The Secretary-General strongly condemns the armed attack in Jammu and Kashmir on 22 April, in which at least 28 people were killed," Stephane Dujarric, spokesman for the Secretary-General, said.Guterres offered his heartfelt condolences to the bereaved families of the victims. "The Secretary-General stresses attacks against civilians are unacceptable under any circumstances," Dujarric said.Terrorists opened fire at a famed meadow near Kashmir's Pahalgam town on Tuesday afternoon, killing 26 people, mostly tourists, in what is the deadliest attack in the Valley since the Pulwama strike in 2019.The 26 victims of the attack included two foreigners - from UAE and Nepal - and two locals. The toll is still being ascertained, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah said while describing the terror attack as "much larger than anything we've seen directed at civilians in recent years".

Canada Sees Record High Advanced Voting, 7.3 Million People Cast Votes



Ottawa.A record 7.3 million people cast ballots over four days of advanced voting in Canada's election, official figures showed Tuesday, in a possible sign of elevated interest in the April 28 poll. Elections Canada said its estimated tally for voting from Friday through Monday marked a 25 percent increase over the 5.8 million advanced ballots cast in the 2021 vote.Canada, a country with a population of 41 million, has 28.9 million eligible voters, Elections Canada said in November. There are further indications the election campaign dominated by threats from US President Donald Trump has galvanized voters, including unusually high ratings for two debates last week.The Liberal Party leader, Prime Minister Mark Carney, is the front-runner, but some polls show Pierre Poilievre's Conservative Party incrementally gaining ground. As of Tuesday, the public broadcaster CBC's poll aggregator gives the Liberals 43.1 percent support, with the Tories at 38.4. The Conservatives have gained one point in the last two weeks, according to the CBC data. Carney, a 60-year-old who previously led the central banks of Canada and Britain, has argued his global experience managing economic crises makes him the ideal candidate to guide Canada through a trade war brought on by Trump's tariffs. Poilievre meanwhile says that lacklustre growth under ex-premier Justin Trudeau's decade in power left Canada vulnerable to Trump and the country cannot afford a fourth consecutive Liberal government. Most Canadian elections are multi-party battles with the left-wing New Democratic Party and Quebec separatist Bloc Quebecois playing crucial roles in the make-up of parliament. This year, polling points to a two-party Liberal-Conservative race, with smaller parties facing significant set backs.

World Economic Forum probes founder Klaus Schwab after alleged misconduct

WORLD.The World Economic Forum (WEF) said that it has opened an investigation into its founder, Klaus Schwab, after a whistleblower's serious allegations against him. The allegations emerged just a day ago when Schwab, 87, revealed he would step down as chairperson with immediate effect without providing any reasonThe Wall Street Journal first broke the news of the investigation, which revealed that an anonymous letter was received by the WEF board last week. The letter complained about the governance and workplace culture of the organisation. It claimed that Schwab and his family combined their personal affairs with WEF resources without any supervision.A spokesperson for the WEF said, "The World Economic Forum takes these allegations seriously, but we want to emphasise that they remain unproven at this stage. We will await the outcome of the investigation before making any further comments."According to the Wall Street Journal, the Schwab family has denied the allegations made in the whistleblower letter. The representative of the family also disclosed that Klaus Schwab intends to sue the author of the anonymous letter and all those who disseminate these false accusations. WHY WEF IS BEING CRITICISED The WEF, particularly its headline-grabbing annual gathering in Davos, has long been accused of being an elitist event that turns a blind eye to the problems of ordinary individuals. There have been increasingly mounting reports on the internal culture at the forum too, with some labelling it a culture of harassment and discrimination.In reaction to these accusations, the WEF's board previously retained a law firm to probe the organisation's work environment. Nevertheless, the WEF has denied these claims consistently.

Canada Elections: Mark Carney Promises To Protect Quebec Voters From Trump

Polls show the ruling Liberals have a narrow lead over the Conservatives ahead of an April 28 election that Carney says is one of the most crucial in Canada's history.

Quebec.Canadian Prime Minister Mark Carney took his election campaign to Quebec on Tuesday, saying only he could protect the predominantly French-speaking province from US President Donald Trump. Polls show the ruling Liberals have a narrow lead over the Conservatives ahead of an April 28 election that Carney says is one of the most crucial in Canada's history.Any party wishing to win power must do well in Quebec, which has the second-largest

number of seats in the House of Commons after Ontario and is home to an independence movement dedicated to protecting the role of French and local culture.Trump has imposed tariffs on imports from Canada and mused about annexing the country."This threat is not only an economic threat, it is an existential threat. To be clear, President Trump is threatening the distinct identity of Quebecers," Carney said at a campaign event in the city of Trois-Rivieres."We'll be able to protect Quebec, protect our sovereignty and build Canada strong ... if you want a strong government that will defend Quebec and stand up to Donald Trump, you must vote for that," he said, reiterating calls for a strong mandate.Trois-Rivieres, one of several Quebec parliamentary constituencies where three and sometimes four parties are contesting the vote, is a key Liberal target. In the 2021 election, the separatist Bloc Quebecois won Trois-Rivieres with 29.5%



of the vote, ahead of the Conservatives' 29.4% and the Liberals' 28.6%. Liberal campaign workers on the ground say there are clear signs that Bloc supporters will switch their votes because they see Carney as the best person to stand up to Trump.A rolling three-day Nanos poll released on Tuesday put the Liberals at 42.6% public support nationally, with the

Conservatives at 37.1%. The left-leaning New Democrats, who compete with the Liberals for the center-left vote, trailed at 10.4%.Such a result on Election Day would give the Liberals a majority of the 343 seats in the House of Commons.The Nanos poll of 1,308 people was carried out from April 19 to 21 and is considered accurate to within 2.7 percentage points, 19 times out of 20.The Conservatives issued their economic plan on Tuesday, which focused on tax cuts and reduced spending. The plan calls for a budget deficit of C\$31.4 billion in 2025-26, less than the C\$42.2 billion the government forecast in December.The plan would "reverse the disastrous Liberal record, cut the cost of food and housing, let you keep more of what you earn and kill inflation so your dollar goes further" the party said in a statement.Carney said a Liberal government could restore a fiscal surplus in four or five years if all goes to plan. A government mandate lasts up to four years.

Sudden Drop In Income": WHO Announces Layoffs Amid US Funding Cuts

Geneva, Switzerland.The World Health Organization chief said Tuesday that operations and jobs would be slashed as US funding cuts had left the UN agency with a budget hole of several hundred million dollars."The sudden drop in income has left us with a large salary gap and no choice but to reduce the scale of our work and workforce," Tedros Adhanom Ghebreyesus told member states, according to a transcript of his remarks.The United Nations health agency has been bracing for President Donald Trump's planned full withdrawal of the United States -- by far its largest donor -- next January. The United States gave WHO \$1.3 billion for its 2022-2023 budget, mainly through voluntary contributions for specific projects rather than fixed membership fees.But Washington never paid its 2024 dues, and is not expected to pay its 2025 dues. This has left the WHO preparing a new structure, which Tedros presented to staff and member states on Tuesday. "The refusal of the US to pay its assessed contributions for 2024 and 2025,

combined with reductions in official development assistance by some other countries, means we are facing a salary gap for the 2026-27 biennium of between \$560 and \$650 million," he said.The lower end of that spectrum "represents about 25 percent of staff costs" currently, he said, stressing



though that "that doesn't necessarily mean a 25-percent cut to the number of positions".He did not say how many jobs would be lost at the WHO, which employ more than 8,000 people around the world.But he acknowledged that "we will be saying goodbye to a

significant number of colleagues" and vowed to do so "humanely".Tedros insisted that the most significant impact would likely be felt at the organisation's headquarters in Geneva. "We are starting with reductions in senior management," he said."We are reducing the senior leadership team at headquarters from 12 to seven, and the number of departments will be reduced by (more than) half, from 76 to 34," Tedros said.WHO's regional offices would meanwhile be affected "to varying degrees", he said, adding that some country offices in wealthier countries would likely be closed.These are very painful decisions for all of us," Tedros said.The WHO chief insisted the situation could

have been worse. WHO member states agreed in 2022 to significantly increase membership fees and reduce the portion of WHO's budget covered by less reliable and often earmarked voluntary contributions.

Jury rules in favour of NYT in Sarah Palin defamation case

Jury rules New York Times not liable in Palin defamation case Editorial mistake admitted, but judged an honest error Palin loses retrial despite claims of lasting damage

WORLD.A federal jury in Manhattan has once again ruled that the New York Times is not responsible for defaming Sarah Palin in a 2017 editorial. It is the second straight courtroom defeat for the former Alaska governor and vice-presidential candidate.Palin, 61, had sued the newspaper and its then-editorial page editor, James Bennet, for an opinion column published on June 14, 2017.The piece had falsely stated that her political action committee's map could have inspired a mass

shooting in Arizona in 2011, when six were killed and Democratic Congresswoman Gabby Giffords was gravely wounded. MISTAKE UNDER DEADLINE PRESSUREJames Bennet, who edited the article, admitted that he had included the controversial connection between Palin's map and the shooting under tight deadlines. The editorial, America's Lethal Politics, implied a link between political violence and the tragic incident.However, the Times quickly accepted their mistake and released a correction in just 14 hours after their piece was published on their website. The correction had clarified that they found no indication of linking Palin's political map with the shooting. But even then, Palin's attorneys were adamant that this was insufficient and came from nowhere when the statement failed to specify Palin's name. The attorneys accused the

blunder of transcending oversight but having a direct, real, hurtful impact upon her reputation.During closing arguments, Times lawyer Felicia Ellsworth stated Palin, being a public figure herself, had a high threshold to clear in establishing defamation."To win this case, Governor Palin needs to prove that the New York Times and James Bennet did not care about the truth," Ellsworth said. "There has not been one shred of evidence showing anything other than an honest mistake." Palin's lawyer, Ken Turkel, disagreed. "This is not an honest mistake about a passing reference," Turkel said. "For her, it was a life-changer." Palin had already lost this case once in 2022, but the ruling was reversed by a federal appeals court because of mistakes committed by the trial judge. The case was retried, resulting in the most recent jury verdict in favour of the

it'll be", adding that it's a "process that's going to go pretty quickly."When asked whether the tariffs on Chinese imports will come down, Trump said, "It'll come down substantially. But it won't be zero." "145 per cent is very high, and it won't be that high...It got up to there [because] we were talking about fentanyl...It will come down substantially, but it won't be zero," the American commander in chief said, referring to an emergency he declared over the smuggling of the drug into the US.He further said that future tariffs "will not be anywhere near that number."The American leader's conciliatory new tone on the matter of his trade policy comes as the International Monetary Fund (IMF) slashed its global growth forecasts, predicting a higher risk of recession in the US as Trump's trade war pushes the global economy into a "significant slowdown". Meanwhile, the White House continued insisting that Trump's tariffs have proved to be a success despite record drops in financial markets and worldwide recession fears. White House Press Secretary Karoline Leavitt said the whole world was beating down Trump's door to strike bilateral trade deals as a result of the President's actions. Trade War With ChinaSo far, US President Trump has imposed tariffs as high as 145 per cent on imports from China. Other countries are facing a blanket 10 per cent US tariffuntil July.



"Undue Government Intrusion": US After Colleges Unite Against Trump

Washington, United States.The White House on Tuesday brushed off criticism levied by dozens of US universities and colleges that accused the Trump administration of unprecedented "political interference" in American academia. More than 100 educational institutions issued a joint letter earlier Tuesday condemning President Donald Trump's undue "intrusion."The move comes a day after Harvard University sued the Trump administration, which has threatened to cut funding and impose outside political supervision."The president has made it quite clear that it's Harvard who has put themselves in a position to lose their own funding by not obeying federal law, and we expect all colleges and universities who are receiving taxpayer funds to abide by federal law," Trump spokeswoman Karoline Leavitt said told reporters.The educational facilities -- including Ivy League institutions Princeton and Brown -- said in the letter that they spoke with "one voice against the unprecedented

government overreach and political interference now endangering American higher education.""We are open to constructive reform and do not oppose legitimate government oversight. However, we must oppose undue government intrusion," it said, adding: "We must reject the coercive use of public research funding."Trump has sought to bring several prestigious universities to heel over claims they tolerated campus anti-Semitism, threatening their budgets, tax-exempt status and the enrolment of foreign students.The letter said the schools were committed to serving as centers where "faculty, students, and staff are free to exchange ideas and opinions across a full range of viewpoints without fear of retribution, censorship, or deportation." Harvard lawsuitTrump's war against universities has seen him threaten to cut federal funding over policies meant to encourage diversity among students and staff.The Republican president has also pursued a wide-ranging immigration

crackdown that has expanded to foreign students, revoking their visas, often for little or no reason.The White House has publicly justified its campaign against universities as a reaction to unchecked anti-



Semitism and the desire to reverse diversity programs aimed at addressing historical oppression of minorities.Leavitt told reporters that Trump was "not going to tolerate illegal harassment and violence towards Jewish American students or students of any faith on our campuses across the country." "We will be responding

to the lawsuit in court," she added.The administration claims protests against Israel's war in Gaza that swept across US college campuses last year were rife with anti-Semitism.Many American universities, including Harvard, cracked down on the protests over the allegations at the time.Several top institutions, including Columbia University, have also bowed to demands from the Trump administration, which claims the educational elite is too left-wing. In the case of Harvard, the White House is seeking unprecedented levels of government control over admissions and hiring practices at the country's oldest and wealthiest university.But Harvard rejected the government's demands, prompting the administration last week to order the freezing of \$2.2 billion in federal funding to the institution.In its lawsuit, Harvard calls for the freezing of funds and conditions imposed on federal grants to be declared unlawful, as well as for the Trump administration to pay the institution's costs.

NEWS BOX

IPL 2025: Players to wear black armbands to pay homage to Pahalgam attack victims

New Delhi. The BCCI (Board of Control for Cricket in India) will be paying tribute to the victims of the Pahalgam terror attack during Match 41 of the Indian Premier League 2025 (IPL 2025) between Sunrisers Hyderabad (SRH) and Mumbai Indians (MI) on Wednesday, April 23 at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. The tragic incident, which took the lives of 26 people, including two foreign nationals, has sent shockwaves throughout the entire country. In memory of the victims, players and umpires will be wearing black armbands and will also stand for a minute of silence before the match. Moreover, no cheerleaders will be present in the ground as austerity measures will be maintained throughout the game. The attack on the innocent tourists has received widespread condemnation from top world leaders, and several Indian cricketers have also expressed their solidarity with the families of the victims. Virat Kohli, Hardik Pandya, KL Rahul and Shubman Gill have condemned the attack



through their social media accounts. It's not the first time that the BCCI is standing in solidarity with the victims of a terrorist attack, as back in 2019, the cricketing body decided not to hold the opening ceremony for the IPL's 12th season. The officials instead decided to donate the money for the welfare of the families of the victims. Stay updated on IPL 2025 with India Today! Get match schedules, team squads, live score, and the latest IPL points table for CSK, MI, RCB, KKR, SRH, LSG, DC, GT, PBKS, and RR. Plus, keep track of the top contenders for the IPL Orange Cap and Purple Cap. Don't miss a

Too many changes, weird calls: How Rishabh Pant's LSG fell apart in revenge clash

Rishabh Pant's Lucknow Super Giants (LSG) had the opportunity to climb to second in the IPL 2025 points table. But that prospect quickly faded after the Delhi Capitals (DC) handed them a comprehensive eight-wicket defeat on Tuesday, April 22, at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow. At the halfway mark of the LSG innings, the hosts appeared to be in cruise control. Openers Aiden Markram and Mitchell Marsh laid a solid foundation for power-hitters like Pant, Nicholas Pooran, and David Miller. However, once Markram departed for a well-made 52, the innings lost momentum. LSG could muster only 72 runs in the final 10 overs, finishing at 159 for six. One of the



most puzzling decisions was skipper Rishabh Pant's demotion to No. 7. He came out to bat with just two balls remaining and was dismissed for a duck, raising questions about the team's strategy. LSG's bowlers also failed to make an impact as Abhishek Porel and KL Rahul both scored half-centuries, steering Delhi to victory with 13 balls to spare. Earlier in the tournament, LSG had narrowly lost to DC by a single run, with Ashutosh Sharma's late fireworks proving decisive. Given a chance to settle the score, the Super Giants instead faltered again—this time, collapsing under pressure in what was expected to be a revenge match. 'Seems like Pant is under pressure' Former wicketkeeper Mark Boucher didn't hold back in his assessment of the Super Giants' performance, especially after the dismissals of Aiden Markram and Nicholas Pooran. He was critical of the team's tactical choices, stating that LSG got it completely wrong in the latter half of their innings. Boucher questioned the omission of Ayush Badoni from the starting XI, arguing that the in-form batter should have played ahead of Abdul Samad.

No cricket with Pakistan': Shreevats Goswami's plea to BCCI after Pahalgam attack

- India and Pakistan don't hold bilateral relations since 2013
- The two teams face off in only ICC events
- India last visited Pakistan for Asia Cup 2008

New Delhi. Former cricketer Shreevats Goswami has urged the BCCI (Board of Control for Cricket in India) to bring an end to all cricketing ties with Pakistan in the wake of the terrorist attack in Jammu & Kashmir's Pahalgam. As many as 26 people have died in the attack on tourists perpetrated by the members of The Resistance Front—an offshoot of the proscribed terror group Lashkar-e-Taiba (LeT). The incident has sent shockwaves throughout the country, with people



demanding strong action to safeguard the lives of citizens in Jammu & Kashmir. Shreevats Goswami has also condemned the incident in a strongly worded post on his social media account. The former wicketkeeper batter has asked the BCCI to stop playing cricket with Pakistan and asked for a response not with bat and ball but with resolve and dignity. "SAY NO TO CRICKET! And this is exactly why I say - you don't play cricket with Pakistan. Not now. Not ever. When BCCI or the government refused to send India to the

Champions Trophy in Pakistan, some had the audacity to say, 'Oh, but sport should rise above politics.' Really? Because from where I stand, murdering innocent Indians seems to be their national sport. And if that's how they play - then it's time we respond in a language they truly understand. Not with bats and balls. But with resolve. With dignity. With zero tolerance," wrote Goswami in a long post on his X account. Furthermore, he recalled his recent visit to Kashmir and sympathised with the locals, saying that it's not a time to stay silent. "I'm furious. I'm

devastated. Just a few months ago, I was in Kashmir for the Legends League - I walked through Pahalgam, met the locals, saw hope returning to their eyes. It felt like peace had finally found its way back. And now... this bloodshed again. It breaks something inside you. It makes you question how many more times we're expected to stay silent, stay "sporting," while our people die. No more. Not this time," he added. It remains to be seen what decision the BCCI (Board of Control for Cricket in India) and the Indian government take with regard to cricketing ties with Pakistan in the aftermath of the terror attack. The two teams haven't played a bilateral series since 2013 and only face off in multinational events at neutral venues. India last visited Pakistan for the Asia Cup 2008, while Pakistan last came to India for the ODI World Cup 2023. Recently, India refused to travel to Pakistan for the ICC Champions Trophy 2025 and played all of their matches at a neutral venue in Dubai. Later this year, India will also be hosting the Women's World Cup in October. As per the agreement between the two cricketing boards, they will not travel to each other's country for ICC events till 2028. Hence, Pakistan will be playing their matches at a neutral venue during the tournament.

Athletics Federation Cup: National record for Dev Meena; Rupal, Jyothi shine

CHENNAI. Pole vaulter Dev Meena from Madhya Pradesh climbed new heights at the National Federation Senior Athletics Competition here on Tuesday. Clinching the gold after easing past 5.35m, Meena has re-written his own national record of 5.30 set in Dehradun in February this year.

However, despite creating a national record, Meena was disappointed for not attaining the Asian Championships qualifying norm, missing it by just 0.16m set by the Athletics Federation of India. "I am slightly disappointed that I couldn't make the cut for the championship. But beyond that, I was concerned of a potential injury if I pushed forth and stopped here as my coach suggested," Meena told reporters. Day 2 was also a showdown for quartermilers in both women and men's categories. Rupal Chaudhary of Uttar Pradesh and Vishal TK of Tamil Nadu bagged gold. Rupal clocked 52.55s, while Vishal 46.19s.

There was a slight drizzle when the six of the eight finalists in women's 400m breached the



53.80 mark set for Asian meet qualification. Just like her gold in Indian Open last month, Rupal with her quick strides, took the lead from Vithya Ramraj of Tamil Nadu who led in the initial 200m. Kerala's Sneha K, finished third. In 400m men's Jay Kumar of Delhi clinched silver and Manu TS of Kerala settled for bronze. National record holder Mohammad Anas Yahiya, who finished first in heats 1 on Monday withdrew before the semi finals of the competition and Amoj Jacob, former Asian champion who was also a favourite did not start in the finals. Amoj pulled out during the final stretch at the Indian Open Athletics held in Chennai last week, while Mohammad Anas did not start in the final. In 110m hurdles men, 2023 champion and national record holder Tejas Shirse of Maharashtra finished first with a timing of 13.65s, while in women's 100m hurdles, national record holder Jyothi Yarraji won gold and secured her spot in the Asian championship touching the finish line at 13.23s.

Manchester City beat Villa: Pep Guardiola calls season bad despite UCL hopes alive

New Delhi. Manchester City manager Pep Guardiola termed the win over Aston Villa as important, while adding that the club's season has been awful and 'it doesn't matter if we reach the (FA Cup) final or qualification for the Champions League.'

Matheus Nunes scored the winner in stoppage time at the Etihad Stadium after Bernardo Silva's early goal for City was cancelled out by Marcus Rashford's penalty. City jumped to third place in the Premier League table with four games remaining, while Villa were left two points behind in seventh place. A top-five finish in the Premier League would secure European Cup football for Manchester City next season. This season has been bad," Guardiola said. "It doesn't matter whether we reach the (FA Cup) final, or qualification



for the Champions League. The reality is that what determines, what makes you feel the season is good is the Premier League, not the Champions League, not FA Cups. It's that consistency in the Premier League. "But it happens, sometimes you have bad seasons. The level of the teams (in the Premier League) is outstanding." Guardiola had referred to the last five league matches as

"finals" in the lead-up to the game, with City hosting Wolves and Bournemouth before facing Southampton and Fulham. Ruben Dias highlighted the importance of their comeback win over Villa. The Portuguese defender said that securing Champions League football was more important than the FA Cup.

Dias said: "They are on the run to the top five with us. Special game to get three points. Four games to go and all of them will be massively important. We keep on going.

"We know how tight it is and how tight it will be until the end. I can't quantify how important today was." This means everything to us. We know exactly what circumstances we are in; top four or five means everything. This is our main trophy. We have the FA Cup and Club World Cup but this is everything to us."

Pahalgam terror attack: No fireworks, cheerleaders in MI vs SRH IPL match; players to sport black armbands

- Terrorists opened fire on civilians at the popular tourist location in south Kashmir on Tuesday, killing at least 26 persons and injuring several others.

HYDERABAD. The players of Sunrisers Hyderabad and Mumbai Indians will wear black armbands during their IPL match which will not feature cheerleaders and fireworks here on Wednesday to mourn the victims of the terrorist attack in Pahalgam that caused 26 deaths.

The teams will also observe a minute's silence to pay their respects to those affected by the incident that has drawn



international condemnation. "The players of two teams will wear black armbands and observe a minute's silence in memory of all those who lost their lives in the

terrorist attack in Kashmir's Pahalgam," a BCCI source told PTL. "As a mark of respect there would be no cheerleaders on the sidelines of MI vs SRH game. No crackers will be burst," he added.

Terrorists opened fire on civilians at the popular tourist location in south Kashmir on Tuesday, killing at least 26 persons and injuring several others.

The Resistance Front (TRF), which is a part of the banned Pakistan-based Lashkar-e-Taiba (LeT) terror group, claimed responsibility for the attack. The attack has drawn strong condemnation from across the world. The Indian cricket team snapped bilateral cricket with Pakistan after the 2008 Mumbai terror attacks and recently refused to tour the country for the Champions Trophy, prompting the ICC to make provisions for a neutral venue in Dubai.

SRH vs MI, IPL 2025 Preview: Predicted XI, team news and Hyderabad pitch conditions

New Delhi. Sunrisers Hyderabad (SRH) will be up for revenge as they take on Mumbai Indians (MI) in Match 41 of the Indian Premier League 2025 (IPL 2025) on Wednesday, April 23 at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad. The Pat Cummins-led side were recently outclassed by the five-time champions away from home as they lost by four wickets. SRH have failed to live up to the expectations this season, having won just two matches out of seven so far. They're teetering at the second-last (ninth) position on the points table with just four points from seven matches. The over-reliance on their famed opening duo of Abhishek Sharma and Travis Head has exposed large gaping holes in their batting order. The bowling has also looked completely out of sorts, with veteran pacer Mohammed Shami failing to live up to the expectations. Harshal Patel and Eshan Malinga have been the only positives for

SRH on the bowling front, and they will once again rely on them heavily in the upcoming fixture. On the other hand, Mumbai Indians have finally injected life back into their campaign after a sluggish start. MI began the season in their usual fashion, having won just one match out of five. The Hardik Pandya-led side had a special affair with number 12 as it turned out to be their losing margin against Lucknow Super Giants (LSG) and Royal Challengers Bengaluru (RCB) as they lost both matches by 12 runs each. However, the same number became the reason for their comeback in the season as they registered a miraculous 12-run win over Delhi Capitals (DC). Furthermore, clinical victories over SRH and Chennai Super Kings (CSK) has helped MI build a winning momentum which could prove to be disastrous for the rest of the teams. The five-time champions will be eager to once again sweep aside SRH in the upcoming fixture



and climb higher on the points table. Mumbai hold the edge over SRH in head-to-head battles having won 14 out of 24 games played between the two teams.

SRH vs MI: TEAM NEWS

Karn Sharma injured his finger in the previous fixture against SRH while fielding. It remains to be seen if he will be available for the upcoming encounter. Meanwhile, there are no injury concerns in the SRH camp.

SRH vs MI: PREDICTED PLAYING XIs and

IMPACTSUBS

Mumbai Indians: Ryan Rickelton (wk), Will Jacks, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Hardik Pandya (c), Naman Dhir, Mitchell Santner, Deepak Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Ashwani Kumar

Impact Sub: Rohit Sharma

Sunrisers Hyderabad: Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan, Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen (wk), Aniket Verma, Abhinav Manohar, Pat Cummins (c), Harshal Patel, Zeeshan Ansari, Mohammed Shami

Impact Sub: Eshan Malinga

SRH vs MI: Weather and Lucknow Pitch Prediction: The pitch at the Rajiv Gandhi International Stadium has been a graveyard for bowlers as scores in north of 220 have been a regular occurrence at the venue. The surface is likely to remain the same for the upcoming clash as well as batters will enjoy stroke-making on the belter of a track.



When Sonam Kapoor

Was SLAMMED For Calling Aishwarya Rai 'Aunty'; Later Denied It



In 2009, Sonam Kapoor said something about Aishwarya Rai that sparked widespread outrage among fans. In an interview, she referred to Aishwarya, then 36, as “aunty” and reasoned it out by saying that the actor has worked with her father, Anil Kapoor. Her comment didn’t sit well with Aishwarya’s fans, and she was brutally trolled. After the backlash, Sonam denied making any such comment altogether and praised the Devdas actor.

Why did Sonam Kapoor call Aishwarya Rai ‘aunty’?
It so happened that back in the day Aishwarya was replaced as the brand ambassador of a popular beauty brand by Sonam. Some reports stated that it was Aishwarya who had backed off, giving the opportunity to the Delhi 6 actor. When asked about it, Sonam referred to Aishwarya and called her “aunty from another generation”. This statement drew widespread flak. Soon after, Sonam was asked about her “aunty” remark. She defended her statement and said, “Aish has worked with my dad so I have to call her aunty na!” She referred to Aishwarya co-starring with Anil Kapoor in films such as Taal, Hamara Dil Aapke Paas Hai, and others. That too, created trouble for the actor.

However, she soon went on deny that she would never call Aishwarya “aunty”. In another interview, Sonam said, “It’s all gossip. I never said any of that. I don’t want to remark on it anymore. A lot has been printed and said and it’s all turn into very untidy and filthy, and I don’t wish to get into it anymore. I really respect Abhishek as a person and had one of my best experiences working in Delhi 6. Aishwarya Rai is Aishwarya Rai. I never said that. I would address her in a deferential way, but I would never call her aunty.”

Sonam received flak for her comment
This controversy often resurfaces on social media. Years back, Sonam-Aishwarya’s controversy went viral on Reddit. An angry user wrote, “You need to have a career for someone to destroy it.” Yet another netizen commented, “So by that logic, Salman would be an uncle since he co-starred with Anil in many movies. How come she did a rom-com with Salman Uncle in Prem Ratan...?? She also worked with Abhishek in Delhi 6, who’s apparently husband of Aunty Aish. She was paired with Bobby Deol in Thank you although Bobby did a romantic movie with Aunty Aish: Aur Pyaar Hogaya na, back in 1997. The list goes on and on.

Imtiaz Ali Reveals REAL Reason Why Bobby Deol Was Removed From Jab We Met: 'Voh Wait Kar Raha Tha'



Bobby Deol recently revealed he was “really upset” after being abruptly removed from Jab We Met, despite initiating its early development with Kareena Kapoor Khan and director Imtiaz Ali. Amid this, an old interview of Imtiaz Ali is doing the rounds on social media. While speaking to The Lallantop, Imtiaz recalled why Bobby was left out of the film. Imtiaz Ali said, “Jab We Met ko Bobby Deol ke saath banane ka plan kar raha tha. Start kari picture but usko kuch aur offers mil rahe the, kuch bade directors ke saath. Toh voh wait kar raha tha. Keh raha tha ki iske baad kar lenge, uske baad kar lenge. Toh, karte karte ek aisa waqt aagaya jo mujhe laga ki ab yeh theek nahi lag raha.”

Imtiaz added, “Bohot waqt beet chuka hai kyuki vaise bhi, 5 saal tak maine ek hi film ki hai. Uske baad bhi ek do saal tak main kuch nahi kar raha tha. Toh matlab financially and even in life, you want to do things. Toh maine bola Bobby yeh film nahi banate hain. Let us decide this today. Let us shake our hands ki film nahi banate kyuki humara ek doosre ke saath sahi nahi rahega.”

Imtiaz’s interview has resurfaced amid Bobby Deol’s recent revelation of feeling hurt. Speaking to Instant Bollywood, Bobby shared how he first discovered the script while watching a rush print of Socha Na Tha, which Imtiaz was directing with Bobby’s cousin Abhay Deol. Impressed, Bobby urged Imtiaz to write a film for him, which eventually evolved into Jab We Met. “I tried really hard to make that film (Jab We Met) happen; I reached out to a lot of people,” he said. Bobby claimed that he played a major role in bringing the production house Shree Ashtavinayak Cine Vision on board. The producers, he said, were interested in working with him but hesitant about backing Imtiaz, who was still relatively new at the time. Bobby pushed for the collaboration and successfully convinced them to give the director a shot. He also reached out to Kareena Kapoor Khan through a contact to offer her the lead role, but she initially declined. Preity Zinta was also approached, but turned it down, saying she would consider it at a later time.

Anshul Garg Asks Fans To Suggest Title For Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa's 'Intense Love Story'



Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa starrer upcoming romance film has already gone on floors, with debutant producer Anshul Garg on board for the project. Taking to his Instagram handle, Garg reached out to his fans to suggest title ideas for the film, which he described as an “intense love story.” Garg also shared a picture with the lead actors along with other team members from the sets of his film. While Harshvardhan and Sonam could be seen dressed up in their respective characters, director Milap Zaveri also joined the frame for the picture. “Suggest me a name for this intense love story! Reading all comments!” Anshul Garg wrote in the caption.

Fans wasted no time sharing their reactions, along with a couple of suggestions for the film’s title. One wrote, “Diwaniyat will be a very beautiful story, and this unique team and its actors will make the story much more interesting,” while another added, “Raqeeb or Bekhudi? Just going by the current title.” “It seems to me that Deewaniyat is a good name for a love story ... But if you think about it, you can come up with more options,” a fan added. A section of fans even suggested that Garg name the film Sanam Teri Kasam 2. With multiple reports touting the film title as Deewaniyat, the makers are yet to officially confirm the same.

Last week, Desi Movies Factory announced the film, revealing the debut of music producer Anshul Garg into the world of cinema. “With seetis, taalis, masala, music, romance, and mass mayhem, we present Anshul Garg’s ‘Production No. 1,’ co-produced by Raghav Sharma, written and directed by Milap Milan Zaveri, starring Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa, and co-written by Mushtaq Shiekh!” the makers mentioned. The film will be released in 2025. The team has started shooting for the film in Mumbai, with Garg dropping the first pictures on his Instagram handle.

Speaking on the same, Garg expressed his views on his debut film as a producer. “I have always believed in stories that connect emotionally, and I believe this film is the right project to begin the journey. It’s a film where music plays a central narrative role—the kind of story where songs don’t just support the plot, they carry it forward,” he said, as quoted by The Times of India. Harshvardhan Rane also shared how Anshul Garg’s vision has been “clear” for the film, which he describes as inspiring.



Disha Parmar

Shares Adorable Glimpses From Her Day Out With Daughter Navya

Disha Parmar has been enjoying the best phase of her life — motherhood. The Television actress is a doting mom to a daughter, named Navya, whom she shares with her husband and singer Rahul Vaidya. She often treats her Instafam with adorable glimpses of her baby. Recently, the Bade Achhe Lagte Hain 2 fame dropped a couple of pictures from her day out with Navya, making the fans go gaga over their bond.

Taking to Instagram, Disha posted a couple of selfies, wherein the mother-daughter duo is seen enjoying a relaxing day under the trees on a bright sunny day. In the snapshots, the actress held her daughter close, as they appeared relaxed and happy. Navya looked straight into the camera with a slight smile on her face.

Both of them kept it casual. As Disha opted for a white T-shirt paired with huge brown shades, Navya looked cute in a light green top. Sharing the pictures, she wrote in the caption, “It’s Navu’s World & mumma is just living in it. #19MonthsToday.” In no time, the comment section was flooded with reactions from her fans and admirers. An Instagram user wrote, “Awwdorable.” Another commented, “So sweet and very cute.” One of them stated, “Two Cuties in one frame.”

Disha tied the knot with singer Rahul Vaidya on July 16, 2021, in Mumbai. The marriage was an intimate affair with just close friends

and family members in attendance. The couple welcomed their little bundle of joy, Navya, in September 2023. On the work front, Disha is a popular face of the Television industry and has appeared in popular shows including Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara and



Woh Apna Sa. She was last seen in the TV show Bade Achhe Lagte Hain Season 3, wherein she portrayed the role of Dr Priya Sood. Backed by Ektaa Kapoor, the show also featured Nakkul Mehta, Supriya Shukla and Shrishti Jain in the lead roles.

The actress took a break from acting after welcoming her daughter in 2023. She is yet to announce her next project. Rahul, on the other hand, is currently seen in Laughter Chefs: Unlimited Entertainment Season 2.